

केंद्र से धनराशि प्राप्त करने के लिए राज्यों को समग्र शिक्षा मानदंडों का पालन करना होगा

खबरों में क्यों?

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दोहराया है कि केंद्र सरकार से धनराशि प्राप्त करने के लिए राज्यों को समग्र शिक्षा योजना (Samagra Shiksha Scheme) की सभी शर्तों को पूरा करना होगा। इनमें उपयोगिता प्रमाण पत्र (Utilisation Certificates), लेखा परीक्षा रिपोर्ट (Audit Reports), प्रगति रिपोर्ट, और राज्य का योगदान जमा करना, साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के कार्यान्वयन मानदंडों का अनुपालन करना शामिल है। संसद में कुछ राज्यों के लिए Rs.1,160.52 करोड़ के तंबित बकाये पर प्रकाश डाला गया है।



समग्र शिक्षा योजना के बारे में

समग्र शिक्षा योजना एक एकीकृत स्कूली शिक्षा कार्यक्रम है जिसे 2018 में लॉन्च किया गया था। यह प्री-स्कूल से कक्षा XII तक की शिक्षा को कवर करता है, जिसका लक्ष्य समावेशी, न्यायसंगत और वहनीय (Affordable) शिक्षा प्रदान करना है।

- शामिल योजनाएँ (Subsumed Schemes):** इसने सर्व शिक्षा अभियान (SSA), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA), और शिक्षक शिक्षा (TE) योजनाओं को समाहित कर दिया है।
- कवरेज:** यह सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 1.16 मिलियन स्कूलों, 156 मिलियन छात्रों, और 5.7 मिलियन शिक्षकों को कवर करती है।
- कार्यान्वयन:** इसे केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme) के रूप में लागू किया जाता है, जिसमें केंद्र और अधिकांश राज्यों के बीच वित्तीयन का अनुपात 60:40 है।

समग्र शिक्षा 2.0 – प्रमुख विशेषताएँ

1. प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT)

पाठ्यपुस्तकों, यूनिफॉर्म और परिवहन भतो सीधे छात्रों के बैंक खातों में हस्तांतरित किए जाते हैं।

2. NEP 2020 की सिफारिशों पर आधारित समर्थन

- भारतीय भाषाओं के लिए समर्थन:** शिक्षकों की नियुक्ति, प्रशिक्षण, और दिमांगी शिक्षण सामग्री के माध्यम से भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना।
- प्री-प्राइमरी शिक्षा के लिए वित्तीयन:** इसमें शिक्षण सामग्री, स्वदेशी खिलौने, और खेल-आधारित गतिविधियों के लिए धन शामिल है।
- प्री-प्राइमरी शिक्षकों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए मार्टर ट्रेनरों की व्यवस्था।**

3. निपुण भारत पहला (NIPUN Bharat Initiative)

बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान (Foundational Literacy and Numeracy) के आकलन के लिए वार्षिक प्रावधान:

- प्रति बच्चा: Rs.500
- प्रति शिक्षक: Rs.150
- प्रति ज़िला: Rs.10-20 लाख



4. डिजिटल पहल

आईसीटी (ICT) लैब, स्मार्ट वलासरूम, वर्चुअल वलासरूम, और डीटीएच (DTH) चैनल को बढ़ावा देना।

5. स्कूल से बाहर के बच्चे

ओपन स्कूलिंग के माध्यम से 16-19 वर्ष के बच्चों को शिक्षा पूरी करने के लिए वित्तीय, व्यावसायिक कौशल (Vocational Skills) पर ध्येय ध्यान।

6. अन्य उपाय

- राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोगों (State Commissions for Protection of Child Rights) को वित्तीय सहायता।
- संज्ञानात्मक (Cognitive), भावात्मक (Affective), और मनोगत्यात्मक (Psychomotor) आकलन के लिए समग्र प्रगति कार्ड (Holistic Progress Card - HPC)।
- परख (PARAKH - राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र) को समर्थन।
- खेल प्रोत्साहन, बैगलेस डे (Bagless Days), स्कूल कॉम्प्लेक्स, कारीगर इंटर्नशिप, और पाठ्यक्रम सुधार।
- सामाजिक ऑडिट (Social Audit): यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी स्कूलों का पाँच वर्षों में ऑडिट हो सके, सालाना 20% स्कूलों को कवर किया जाएगा।



फंडिंग की शर्त

केंद्र से हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए राज्यों को योजना के मानदंडों और NEP 2020 सुधारों का सख्ती से पालन करना आवश्यक है।

UPSC Prelims Practice Questions –

Q1. समग्र शिक्षा योजना (Samagra Shiksha Scheme) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- यह सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा—इन सभी को समाहित करती है।
- यह पूर्व-प्राथमिक से कक्षा 12 तक की स्कूली शिक्षा को कवर करती है।
- यह योजना पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वितापोषित है।
- समग्र शिक्षा 2.0 के तहत पाठ्यपुस्तकें, यूनिफॉर्म और परिवहन भत्ता सीधे छात्रों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से दिया जाता है।

ऊपर दिए गए में से कौन-से कथन सही हैं?

- (A) केवल 1 और 2
(B) केवल 1, 2 और 4
(C) केवल 2, 3 और 4
(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर: (B) केवल 1, 2 और 4



Q2. समग्र शिक्षा योजना के संर्दर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें:

- इसका उद्देश्य समावेशी, न्यायसंगत और किफायती स्कूली शिक्षा प्रदान करना है।
- इसके अंतर्गत निपुण भारत (NIPUN Bharat) पहल बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता (Foundational Literacy & Numeracy) मूल्यांकन के लिए धन उपलब्ध कराती है।
- यह योजना केवल सरकारी विद्यालयों को कवर करती है और सहायता प्राप्त स्कूलों (aided schools) को शामिल नहीं करती।

ऊपर दिए गए में से कौन-सा/से कथन सही हैं/हैं?

- (A) केवल 1
(B) केवल 1 और 2
(C) केवल 2 और 3
(D) उपर्युक्त सभी

उत्तर: (B) केवल 1 और 2

Q3. समग्र शिक्षा 2.0 की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करें:

- पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के लिए शिक्षण-सामग्री और स्थानीय/स्वदेशी खिलौनों हेतु वित्तीय सहायता।
- डिजिटल शिक्षा के लिए ICT लैब, स्मार्ट वलासरूम और वर्चुअल वलासरूम।
- निजी विद्यालयों को अवसंरचना विकास के लिए वित्तीय सहायता।

4. छात्रों के संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोचालित क्षेत्रों के मूल्यांकन हेतु समग्र प्रगति कार्ड (Holistic Progress Cards — HPC)।

ऊपर दिए गए में से कौन-से कथन सही हैं?

- (A) केवल 1 और 2
- (B) केवल 1, 2 और 4
- (C) केवल 2, 3 और 4
- (D) उपर्युक्त सभी

उत्तर: (B) केवल 1, 2 और 4



Q4. समग्र शिक्षा के वित्तपोषण और कार्यान्वयन के संबंध में निम्न में से कौन-सा/से सही हैं?

- 1. यह एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जिसमें अधिकांश राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 का वित्तीय अनुपात है।
- 2. निधियों की रिहाई योजना मानकों के अनुपालन तथा उपयोग प्रमाणपत्र एवं प्रगति रिपोर्ट जमा करने पर निर्भर करती है।
- 3. केंद्र की निधि प्राप्त करने के लिए राज्यों को NEP 2020 के सुधारों को लागू करना अनिवार्य है।

सही विकल्प चुनें:

- (A) केवल 1
- (B) केवल 1 और 2
- (C) 1, 2 और 3
- (D) केवल 2 और 3

उत्तर: (C) 1, 2 और 3

Result Mitra
रिजल्ट का साथी



@resultmitra



www.resultmitra.com



9235313184, 9235440806

